भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1510

जिसका उत्तर सोमवार, 02 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है

इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन अवसंरचना

1510. श्री विजय गोयल:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन अवसंरचना को बढ़ावा देकर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कोई कदम उठा रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो ऐसी परियोजनाओं की समय-सीमा और इनके लिए किए गए बजटीय आवंटन सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री प्रकाश जावड़ेकर)

(क) और (ख): जी, हाँ। सरकार ने भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण (फेम-इंडिया) योजना के चरण-II के माध्यम से इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं। इस योजना का उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना और वाहन संबंधी उत्सर्जन के मुद्दों का समाधान करना है।

यह योजना ₹10,000 करोड़ के बजटीय आवंटन के साथ दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से 3 वर्षों की अवधि के लिए दिल्ली-एनसीआर सहित पूरे भारत के लिए है। सार्वजनिक परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर योजना के तहत अग्रिम प्रोत्साहन दिया जाता है और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जरुरी चार्जिंग अवसंरचना के सृजन की भी सहायता की जाती है। योजना के तहत सार्वजनिक परिवहन के लिए दिल्ली-एनसीआर को ₹250 करोड़ (लगभग) के सरकारी प्रोत्साहन से लगभग 500 इलेक्ट्रिक बसें मंजूर की गई हैं।

******